https://cwc.gov.in/en/Jalansh

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

अंक 4&5

जलांश - नवम्बर -दिसंबर -2024

खंड-07

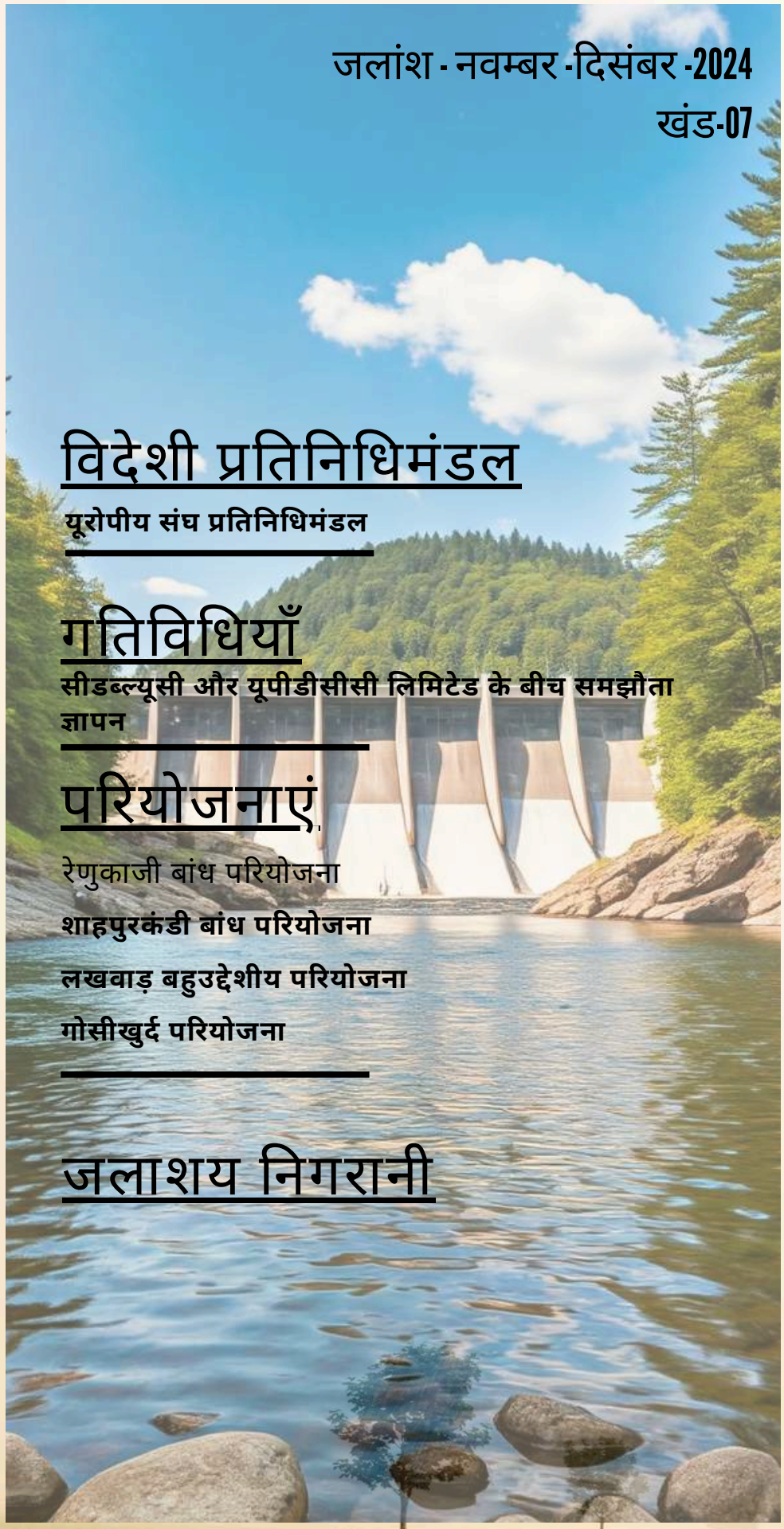

विदेशी प्रतिनिधिमंडल

यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल

गतिविधियाँ

सीडब्ल्यूसी और यूपीडीसीसी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन

परियोजनाएं

रेणुकाजी बांध परियोजना

शाहपुरकंडी बांध परियोजना

लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना

गोसीखुर्द परियोजना

जलाशय निगरानी

विषयसूची

पृष्ठ 1

विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकें:

यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल

पृष्ठ 1-2

परियोजनाओंसे संबंधित बैठकें:

माननीय मंत्री, जलशक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में बैठक

पृष्ठ 3

परियोजनाओंसे संबंधित बैठकें:

बिहार और झारखंड में उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीईसी की 41वीं बैठक

पृष्ठ 4

परियोजनाओं से संबंधित बैठकें:

पुनात्सांगछू- I जलविद्युत परियोजना के दाहिने तट की स्थिरता के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों पर चर्चा

सरहिंद फीडर, राजस्थान फीडर परियोजना, और शाहपुरकंडी बांध परियोजना

कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना

सुबेनरेखा परियोजना, राजीव भीमा लिफ्ट सिंचाई, लोअर भवानी परियोजनाओं का आधुनिकीकरणऔर अन्य परियोजनाओं की समीक्षा

पृष्ठ 5-6

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पृष्ठ 7-8

साइटों/परियोजनाओं का दौरा:

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की पार्बती-II एचईपी (800 मेगावाट)।

गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ की समस्या के संबंध में अजवा बांध और प्रतापपुरा बांध

सुबनसिरी लोअर एचईपी के लिए विशेषज्ञ समूह

विष्णुपुरी बैराज, नांदेड़ , महाराष्ट्र

तिलपाड़ा बैराज

पृष्ठ 9

बांधसुरक्षा अधिनियम, 2021/एनडीएसए

डीआरआईपी चरण-II और III की तकनीकी समिति की तीसरी बैठक

पृष्ठ 10-14

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

देश में बाढ़ की स्थिति - अक्टूबर 2024

पृष्ठभूमि सामग्री/कार्य योजना और आवश्यकताओं केसाथ बाढ़ जलप्लावन मॉड्यूल की प्रस्तुति

बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर प्रगति समीक्षा बैठकें

सीडब्ल्यूपीआरएस के अध्ययन की स्थिति की निगरानी के लिए 9वीं और 10वीं बैठक

एनएचपीए के तहत गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ प्रणाली के संबंध में एईसीओएम के साथ बैठक

एनईएसएसीए द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली / बाढ़ जलप्लावन अध्ययन

विभिन्न अंतर्राज्यीय मुद्दों पर प्रस्तुति

पीएमकेएसवाई योजना की समीक्षा के लिए बैठक

11 उन्नत चरण पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की समीक्षा (उनके सीएडीडब्ल्यूएम घटकों के साथ))

एनएचपी के तहत एकीकृत जलाशय संचालन पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दूसरी तिमाही वार्ता

केंद्रीय जल आयोग और उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।

पृष्ठ 15

जलाशय निगरानी

पृष्ठ 16-17

दीर्घा

अध्यक्ष का संदेश

डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा
अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी

मुझे जलांश के इस संस्करण को प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें हाल के महीनों में केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। नवंबर-दिसंबर 2024 की अवधि में विभिन्न जल प्रबंधन पहलों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और नीतिगत ढाँचों में सक्रिय भागीदारी, चर्चाएँ और उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है।

भारत-यूरोपीय संघ जल पहल (IEWI) चरण-III के अंतर्गत यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में जल प्रबंधन में वैश्विक सहयोग के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। 8वें भारत जल सप्ताह के प्रमुख परिणामों की समीक्षा की गई, जिसमें एकीकृत और टिकाऊ जल प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

जल शक्ति मंत्रालय के मार्गदर्शन में, रेणुकाजी बांध, ग्रैंड एनीकट आधुनिकीकरण योजना, शाहपुरकंडी बांध और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना जैसी कई राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और पनबिजली उत्पादन में सुधार होगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। गोसीखुर्द परियोजना और भूटान में पुनात्संगचू- I पनबिजली परियोजना के बारे में चर्चा में तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया गया और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया गया।

के.ज.आ बाढ़ प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए महानदी, गोदावरी और तापी जैसी प्रमुख नदी घाटियों में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए एनईएसएसी के साथ सहयोग करना आपदा प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण की दिशा में एक और कदम है।

देहरादून में ड्रिप चरण II और III के अंतर्गत तकनीकी समिति की तीसरी बैठक में महत्वपूर्ण तकनीकी, वित्तीय और पर्यावरण सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। विष्णुपुरी बैराज और तिलपारा बैराज जैसे प्रमुख स्थलों पर किए गए आकलन संरचनात्मक सुरक्षा और परिचालन दक्षता बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

के.ज.आ ने अंतर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना और अन्य अंतर-राज्यीय जल बंटवारे के विवादों पर की गई चर्चा, न्यायोचित एवं सतत जल वितरण सुनिश्चित करने के प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

जैसे-जैसे के.ज.आ आगे बढ़ रहा है, उसका ध्यान भी परियोजना निष्पादन में सुधार, बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर स्थिर रहा है। सभी हितधारकों, अधिकारियों और विशेषज्ञों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जाता है जिनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने इस मिशन की सफलता में योगदान दिया है।

आइए हम सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें ।

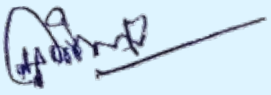

विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें

यूरोपीय संघ प्रतिनिधिमंडल

के. ज.आ के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार वर्मा ने 8 अक्टूबर 2024 को सेवा भवन में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री नवीन कुमार, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के. ज.आ, श्री आनंद मोहन, जेएस (आरडी एंड पीपी), जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और केंद्रीय जल आयोग के अन्य अधिकारी भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधि और जीआईजेड के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने भारत यूरोपीय संघ जल पहल (IEWI) के चरण- III के लिए भविष्यकी कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया और 8वें भारत जल सप्ताह के दौरान आयोजित 6वें भारत यूरोपीय संघ मंच के प्रमुख परिणामों पर चर्चा की।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

माननीय मंत्री, जलशक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में बैठक

भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए चिन्हित राष्ट्रीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी। राष्ट्रीय परियोजना योजना को केंद्रीय अनुदान के रूप में सिंचाई और पेयजल घटक की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नीचे उल्लिखित परियोजनाओं पर चर्चा के लिए दिनांक 15.10.204 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और निम्नलिखित चर्चाएँ हुईं:

रेणुकाजी बांध परियोजना:

रेणुकाजी बांध परियोजना में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मौजूदा जेटन बैराज से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर और गिरि नदी के साथ जोगर-का-खाला के संगम से लगभग 375 मीटर नीचे की ओर 148 मीटर ऊंचा रॉकफिल बांध बनाने की परिकल्पना की गई है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी गिरि पर एक भंडारण योजना है।

इस परियोजना से 40 मेगावाट गौण बिजली पैदा होगी। 498 एमसीएम का सक्रिय भंडारण दिल्ली को 9 महीने (अक्टूबर से जून) के दौरान 23 क्यूमेक्स तक की निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करेगा।

जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति द्वारा 9.12.2019 को आयोजित उनकी 143 वीं बैठक में अनुमोदित रेणुकाजी बांध परियोजना की स्वीकृत लागत 6946.99 करोड़ रुपये (पीएल अक्टूबर 2018) है। परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है और इसे अगस्त, 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बैठक में जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया । बैठक के दौरान रेणुकाजी बांध परियोजना के डिजाइन मुद्दों तथा परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा पर चर्चा की गई।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना:

शाहपुरकंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) रावी नदी पर है, जो रणजीत सागर बांध से 11 किलोमीटर नीचे और माधोपुर हेडवर्क्स से 8 किलोमीटर ऊपर है। इसमें 55.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध, नदी के बाएं किनारे पर 7.70 किलोमीटर लंबा हाइडल चैनल, 2 हेड रेगुलेटर, एक पंजाब में शाहपुरकंडी हाइडल चैनल (बाएं तरफ) को पानी देने और दूसरा जम्मू-कश्मीर में रावी नहर (दाएं तरफ) को पानी देने के लिए निर्माण की परिकल्पना की गई है।

परियोजना से 37173 हेक्टेयर (जम्मू-कश्मीर में 32173 हेक्टेयर + पंजाब में 5000 हेक्टेयर) सिंचाई लाभ होगा तथा 206 मेगावाट (2x99 मेगावाट+ 8 मेगावाट) विद्युत उत्पादनक्षमता होगी।जल संसाधन विभाग , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया । बैठक के दौरान शाहपुरकंडी बांध परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी देने तथा समय पर पूरा करने पर चर्चा की गई।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

व्यय विभागके सचिव की अध्यक्षता में 21.11.2024 को पीआईबी की एक और बैठक आयोजित की गई।बैठक में जल संसाधनविभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान संशोधित लागत की मंजूरी, केन्द्रीय सहायता में वृद्धि तथा परियोजना को दिसंबर, 2025 तक पूरा करने के विस्तार पर चर्चा की गई।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना:

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना में उत्तराखंड में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 330.66 एमसीएम का लाइव स्टोरेज होगा। परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 300 मेगावाट (3X100 मेगावाट) है, जिससे 33,780 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा और 78.83 एमसीएम पेयजल और औद्योगिक जल आपूर्ति होगी। इस परियोजना में लखवार बांध से 13.6 किलोमीटर नीचे कटापाथर बैराज के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) द्वारा किया जाना है। 11-02-2019 को आयोजित 141वीं टीएसी बैठक में लखवार परियोजना को 2018 (पीएल) के अनुसार 5747.17 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर स्वीकार किया गया। परियोजनाको दिसंबर 2031 तक पूराकिया जानाहै।

जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान लखवार एम.पी.पी. के डिजाइन संबंधी मुद्दों तथा समय पर पूरा करने पर चर्चा की गई।

लखवार परियोजना एम.पी.पी. (व्यासी जलाशय के संचालन के बाद) के प्रस्तावित टी.आर.टी. आउटलेट पर अवसादन के कारण के.ज.आ द्वारा दीर्घकालिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त की गई थीं तथा निविदा चरण में प्रस्तावित टी.आर.टी. आउटलेट को बढ़ाने की सलाह दी गई थी। इस संबंध में सी.ई.ए./यू.जे.वी.एन.एल. द्वारा सी/एल. टरबाइन पर इसके प्रभाव के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। इस पृष्ठभूमि में, के.ज.आ तथासी.ई.ए. के बीच 28.11.2024 को एक और बैठक बुलाई गई। बैठक की सह-अध्यक्षता के.ज.आ के सदस्य (डी.एंड.आर.) तथा सी.ई.ए. के सदस्य (हाइड्रो) ने की तथा दोनों संगठनों के संबंधित अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

गोसीखुर्द परियोजना:

महाराष्ट्र राज्य में निर्माणाधीन प्रमुख सिंचाई परियोजना गोसीखुर्द में भंडारा जिले के पौनी तालुका के गोसीखुर्द गांव के पास वैनगंगा नदी पर गेटयुक्त स्पिलवे के साथ मृदा बांधके निर्माण के माध्यम से 2,50,800 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करने की परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना को तत्कालीन योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 7777.84 करोड़ रुपये (डीएसआर 2007-08) के लिए पत्र संख्या 20(13)/2008-डब्ल्यूआर दिनांक 14.05.2008 के तहत मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय परियोजना में घटकों की संगत लागत 4,315.966 करोड़ रुपये थी। इस परियोजना को 2008 तक एआईबीपी के तहत वित्त पोषित किया गया था और फरवरी 2009 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। परियोजना की संशोधित लागत को अंतिम रूप दिया गया था।फास्टट्रैकपरफॉर्मा क्लीयरेंस (एफटीपीसी) के तहत के.ज.आ, नई दिल्ली द्वारा 18,494.57 करोड़ रुपये के लिए ओएम 4/1/2013/एनपी-II/वॉल्यूम-VII/1802-1814दिनांक 11.12.2017 के माध्यम से स्वीकृत किया गया है, जिसकी राष्ट्रीय परियोजना लागत 12,770.09 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की योजना 250800 हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) को पूरा करने के लिए बनाई गई है, जिसमें से 231081 हेक्टेयर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत है। परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि जून-2026 है।

जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग तथा व्यासी केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया । बैठक के दौरान गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना को समय पर पूरा करने के संबंध में चर्चा की गई।

ग्रैंड एनीकट विस्तार और आधुनिकीकरण योजना, तमिलनाडु

तमिलनाडु में ग्रैंड एनीकट विस्तार और आधुनिकीकरण योजना की घोषणा वर्ष 2019-2020 में की गई थी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 13.11.2020 को दी गई और कार्य आदेश 05.02.2021 को जारी किया गया। ₹1082.31 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य ग्रैंड एनीकट नहर में 4,200 क्यूसेक जल की पूर्ण आपूर्ति को बहाल करना है, जिससे इसकी संवहन दक्षता 45% से बढ़कर 61.60% हो जाएगी। इसका उद्देश्य 67,500 एकड़ के अंतर क्षेत्र को पाटकर कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे तंजावुर और पुदुक्कोट्टई जिलों में कुल 2,27,472 एकड़ के आयाकट को लाभ होगा । इस योजना में 101.41 किलोमीटर नहर लाइनिंग, पांच रेगुलेटर, 79 हेड स्लुइस और पाइप स्लुइस की मरम्मत, 24 ड्रॉप, तीन पुल, चार नहर साइफन, दो जलसेतु, 23 साइफन और साइफन जलसेतु, 31.56 किलोमीटर सड़कें, 45.21 किलोमीटर बांध सुदृढ़ीकरण, 7.58 किलोमीटर सुरक्षा दीवारें और 2.8 किलोमीटर रिवेटमेंट जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। अब तक, परियोजना ने ₹1039.75 करोड़ के व्यय के साथ 99.6% कार्य प्रगति और 96% वित्तीय प्रगति हासिल की है। पांच परियोजना पैकेजों में से चार पूरे हो चुके हैं और

एक पूरा होने वाला है। जबकि समझौते की अंतिम तिथि फरवरी 2024 है, संशोधित समापन तिथि 30.04.2024 निर्धारित की गई है, जो पिछली समाप्ति तिथि 23.08.2024 से पहले है। 2022 और 2023 के दौरान मेट्टूर बांध से पानी की अग्रिम रिहाई और 2024 में जल विनियमन अवधि के कारण होने वाली देरी के बावजूद, परियोजना संशोधित समयसीमा तक पूरी होने की राह पर है। लाभान्वित होने वाला आयाकट 1,44,572.32 एकड़ है , जो इस आधुनिकीकरण पहल के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है।

तंजावुर जिले के ओरथानाडु तालुक के चेल्लमपट्टी गांव में ग्रैंड एनीकट कैनाल ड्रॉप नंबर 2 एलएस 62.885 किलोमीटर

तंजावुर जिले के ओरथानाडु तालुक के वेट्टुवक्कोट्टई गांव में एलएस 80.00 किमी से 89.045 किमी- अस्तरण

तंजावुर जिले के ओरथानाडु तालुक में सिल्लाथुर (वेटिकाडु) गांव में महाराजासमुथिरम जलसेतु

बिहार और झारखंड में उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीईसी की 41वीं बैठक

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की बैठक 21.10.2024 को के. ज.आ, नई दिल्ली में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी),के. ज.आ और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग, के.ज.आ मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और वैपकोस के अधिकारियों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण एजेंडा मदों जैसे जलसंसाधन विकास मंत्रालय, बिहार द्वारा भूमि अधिग्रहण कीस्थिति, वैपकोस द्वारा परियोजना केशेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, बिहारभाग (आरडी 68.37 किमी से109.09 किमी) में आरएमसी और इसकी संरचनाओं की लाइनिंग, मरम्मत और निर्माण केकार्य के लिए निविदा कीस्थिति, वितरणके निर्माण के कार्य केलिए निविदा की स्थिति आदि पर चर्चा हुई।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

पुनात्सांगछू- I जलविद्युत परियोजना के दाहिने तट पर स्थिरता के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों पर चर्चा

बैठक में सदस्य (डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) और उनकी टीम, डब्ल्यूएपीसीओएस, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), सीईए, सीएसएमआरएस, विदेश मंत्रालय और भूटान की शाही सरकार ने भाग लिया। बैठक के दौरान, अधिकारियों ने पुनात्सांगचू- I जलविद्युत परियोजना (एचईपी) के दाहिने किनारे की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त उपायों पर चर्चा की।

सरहिंद फीडर, राजस्थान फीडर परियोजना, और शाहपुरकंडी बांध परियोजना

केंद्रीय जलआयोग (के.ज.आ) के अध्यक्षकी अध्यक्षता में 28 नवंबर 2024 को सेवा भवन, नई दिल्लीमें एक बैठकआयोजित की गई। बैठकमें पंजाब सरकार केजल संसाधन विभाग केप्रधान सचिव औरजल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ और जलसंसाधन विभाग, पंजाब सरकार केअधिकारियों ने भागलिया। बैठक काउद्देश्य जल संसाधनविभाग, पंजाब सरकार द्वाराउठाए गए विभिन्नपरियोजनाओं के मुद्दोंकी समीक्षा और चर्चाकरना था ताकिइन परियोजनाओं की प्रगतिमें तेजी लाईजा सके। बैठक के दौरान चर्चा की गई परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

a)सरहिंदफीडर नहर कीरीलाइनिंग

b)राजस्थानफीडर नहर कीरीलाइनिंग

c)शाहपुरकंडी बांध परियोजना

d)सीमावर्तीक्षेत्रों में बीओपी बचाने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान कार्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथाराष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भमें स्थापित अन्य रक्षाअवसंरचनाओं की सुरक्षा

e)सतलुजनदी द्वारा पोषित होने वाली नहरों के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाकी अनुमानित लागत

f)नदीप्रबंधन गतिविधियाँ और सीमावर्तीक्षेत्रों से संबंधितकार्य (आरएमएबीए)

कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना

मौजूदा कोसी परियोजना में भारत-नेपाल सीमा के करीब हनुमान नगर कस्बे के पास स्थित हनुमान नगर बैराज और पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) तथा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर (डब्ल्यूकेएमसी) नामक नहर नेटवर्क शामिल हैं। प्रस्तावित कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना में मौजूदा ईकेएमसी (आरडी 0.0 किमी से आरडी 41.3 किमी) का पुनर्निर्माण और आरडी 41.30 किमी से आरडी 117.50 किमी तक मेची नदी तक विस्तार करना शामिल है, जो महानंदा नदी की एक सहायक नदी है।

ईकेएमसी को मेची नदी तक विस्तारित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से हनुमान नगर बैराज में उपलब्ध जलाशयों के आधार पर खरीफ मौसम (जून से अक्टूबर) के दौरान जल की कमी वाले महानंदा बेसिन कमांड क्षेत्र के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में 2.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सीसीए की सिंचाई करना और कोसी बेसिन के अधिशेष जल का कुछ हिस्सा महानंदा बेसिन में स्थानांतरित करना है।

कोसी-मेची अंतर-राज्यीय परियोजना कीयोजना और डिजाइनसे संबंधित मुद्दों कीसमीक्षा और चर्चाकरने के लिए बिहारसरकार के विकासआयुक्त की अध्यक्षतामें 18.11.2024 को पटना मेंडब्ल्यूआरडी बिहार, एनडब्ल्यूडीए, बीसीडी (एन एंडडब्ल्यू), के.ज.आ (मुख्यालय) और एलजीबीओ, के.ज.आ के अधिकारियों के बीच एकबैठक आयोजित की गईथी।

सुवर्णरेखा परियोजनाओं की समीक्षा, राजीव भीमा लिफ्ट सिंचाई, लोअर भवानी परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और अन्य परियोजनाएं

जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में 18.11.2024 को 7 परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, अध्यक्ष, के.ज.आ, सदस्य,डब्ल्यूपी&पी और प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशकों ने भाग लिया। बैठक में जल शक्ति मंत्री ने निर्देश दिया कि परियोजनाओं के विभिन्न घटकों की संशोधित लागत में वृद्धि के कारणों पर जोर देते हुए परियोजना की लागत (मूल और आगे संशोधित लागत) पर विस्तृत तुलनात्मक नोट उपलब्ध कराया जाए, इसके जवाब में, इस कार्यालय ने अपने पत्र संख्या एन-74074/358/2024-एमओएन(एस) डीटीई दिनांक 12.12.2024 के माध्यम से यही जानकारी प्रदान की।

समीक्षा बैठक के दौरान, स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना के संयुक्त घटक की प्रगति पर चर्चा करने के लिए झारखंड और ओडिशा राज्यों के परियोजना अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	प्रशिक्षण का नाम	अवधियां	प्रतिभागियों की संख्या	उद्देश्य
1	34वां प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)	34 सप्ताह	34	नव नियुक्त सीडब्ल्यूईएस ग्रुप-ए अधिकारियों के लिए
2	जल गुणवत्ता निगरानी एवं मूल्यांकन	एक सप्ताह	33	विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभागों तथा शहरी जल बोर्डों के प्रतिभागी।
3	एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एक सप्ताह	---	आईडब्ल्यूआरएम पर विषयों की विस्तृत श्रृंखला जैसे कि सीमापार जल प्रबंधन, नदी बेसिन मास्टर प्लान के लिए बहु मानदंड विश्लेषण, जल संसाधनों का बेसिन-वार पुनर्मूल्यांकन, राष्ट्रीय जल नीति और रूपरेखा कानून, जल लेखांकन, जल बजट, जल मूल्यांकन और आवंटन, आईडब्ल्यूआरएम में भागीदारी दृष्टिकोण और क्षमता निर्माण की भूमिका आदि।
4	प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)	एक सप्ताह	17	फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) के नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर (जेई)
5	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तहत 'निःशुल्क उपकरणों का उपयोग करते हुए जल विज्ञान मॉडलिंग '	एक सप्ताह	48	कई निःशुल्क और ओपन-सोर्स उपकरणों का अवलोकन, जैसे कि जीआईएस विश्लेषण के लिए क्यूजीआईएस, उपग्रह डेटा विश्लेषण के लिए गूगल अर्थ इंजन
6	हाइड्रोमेट कैडर के सहायक निदेशकों के लिए एमसीटीपी और अतिरिक्त सहायक निदेशकों के लिए एमसीटीपी	07 दिन	05+10=15	अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम
7	जलाशय अवसादन मूल्यांकन और प्रबंधन	एक सप्ताह		राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत प्रशिक्षण
8	जीईएम के माध्यम से खरीद , ई-टेंडरिंग और खरीद चुनौतियां (पूर्वोत्तर हाइड्रोलिक एवं संबद्ध अनुसंधान संस्थान (नेहारी), ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सहयोग से)	एक सप्ताह	--	जेम और ई-टेंडरिंग प्लेटफार्मों के प्रभावी उपयोग में बी.बी. अधिकारियों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाना।

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

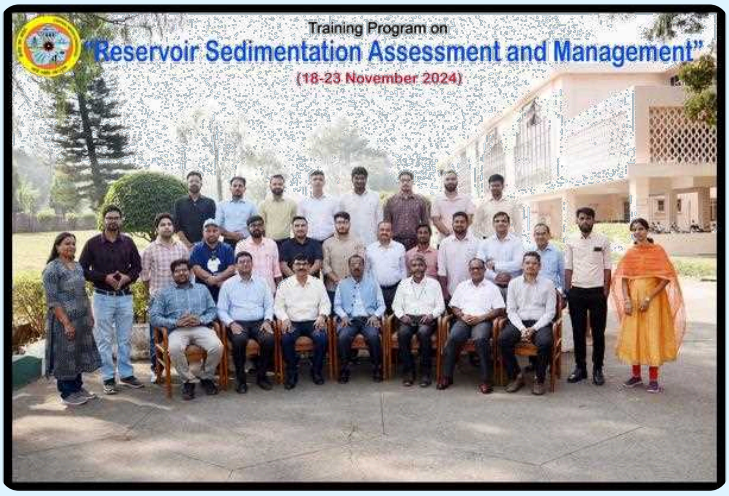

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की पार्बती-II एचईपी (800 मेगावाट)।

एनडीएसए केदिनांक 11.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन केअनुसार, निदेशक और उपनिदेशक, ईएमबी (एन एंडडब्ल्यू) को एनडीएसएकी ओर सेप्रारंभिक भराव सेपहले पार्बती-II एचईपी (800 मेगावाट), एचपी केबांध का निरीक्षणकरने और परियोजनाअधिकारियों द्वारा तैयार प्रारंभिकभराव योजना की समीक्षाकरने के लिएअधिकृत किया गयाथा।

केंद्रीय जलआयोग और एनडीएसएके अधिकारियों की संयुक्तटीम ने 16.10.2024 से 18.10.2024 तक परियोजनाका दौरा किया

गुजरात के वडोदरा शहर में बाढ़ की समस्या के संबंध में अजवा बांध और प्रतापपुरा बांध

श्री विवेकत्रिपाठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिजाइन (एन एंडडब्ल्यू), श्री आलोकपॉल कलसी, निदेशक, डब्ल्यूएसआरएस निदेशालय औरश्री आमिर सुहैल, उप निदेशक, के.ज.आ के साथ-साथ के.ज.आगांधीनगर और वडोदरानगर निगम केअधिकारियों ने 10 अक्टूबर 2024 को अजवाऔर प्रतापुरा जलाशयों औरइन दोनों जलाशयों कोजोड़ने वाली फीडरनहर का दौराकिया।

इस यात्रा का उद्देश्य वडोदरा में हाल ही में आई बाढ़ के कारणों का अध्ययन करना, बाढ़ के चरम को कम करने में ऊपरी जलाशयों के प्रभाव का अध्ययन करना तथा भविष्य में बाढ़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए अल्पकालिकऔर दीर्घकालिक बाढ़ शमन उपायों का सुझाव देना था।

वडोदरा शहर की बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष श्री बी एन नवलावाला की अध्यक्षता में एक और बैठक 11 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई। बैठक में के.ज.आटीम द्वारा सुझाए गएउपायों पर विस्तृतचर्चा हुई।

सुबनसिरी लोअर एचईपी के लिए विशेषज्ञ समूह

श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत, निदेशक, के.ज.आ, नवंबर 2023 में विद्युत मंत्रालय द्वारा सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह के सदस्य हैं। विशेषज्ञ समूह की अंतिम रिपोर्ट 13 नवंबर, 2024 को सीईए द्वारा विद्युत मंत्रालय को सौंपी गई थी। इसके बाद, सीईए ने परियोजना की जमीनी स्थितियों का आकलन करने के लिए 20-22 नवंबर, 2024 तक एक साइट दौरे काआयोजन किया। श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत, निदेशक, के.ज.आ ने सुश्रीमनु दुबे, डीडी, सीएमडीडी (एन एंडडब्ल्यू) के साथइस साइट दौरे मेंभाग लिया ।

विष्णुपुरी बैराज, नांदेड़ , महाराष्ट्र

विष्णुपुरी बैराज, नांदेड़ , महाराष्ट्र एक उच्चस्तरीय बैराज है जोगोदावरी नदी परनिचली गोदावरी परियोजना नामत: शंकररावजीचवन विष्णुपुरी परियोजना (तब एशियाकी दूसरी सबसे बड़ीलिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस)) के एक भाग के रूप में बनाया गयाहै।

डॉ. अजीत माधवराव गोपचड़े, माननीय सांसद, राज्यसभा द्वारा उठाए गए गाद मुद्दे के अनुसरण में, जल शक्ति मंत्रालय ने विष्णुपुरी बैराज में गाद मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक केंद्रीय टीम गठित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, गाद की समस्याके बारे मेंजानकारी एकत्र करने औरउपाय सुझाने के लिएके.ज.आ और सीपीएमयू ड्रिप केअधिकारियों की एकटीम गठित कीगई। जिसके बाद, टीम द्वारा 12.11.2024 को साइट कादौरा किया गया।

तिलपाड़ा बैराज

सीपीएमयू/के.ज.आ, ईएमसी और विश्वबैंक के अधिकारियों की एक टीमने 13.11.2024 को तिलपारा बैराज, पश्चिम बंगालका दौरा किया, ताकि बैराज के निचलेहिस्से में होरहे भूस्खलन के मद्देनजरतत्काल उपचारात्मक उपाय करनेमें पश्चिम बंगाल केअधिकारियों को मार्गदर्शन दिया जा सके।

डीआरआईपी चरण-II और III की तकनीकी समिति की तीसरी बैठक

ड्रिप (डीआरआईपी) चरण II और III की तकनीकी समिति की तीसरी बैठक 18.10.2024 को श्री भोपालसिंह, सदस्य (डी एंडआर), के.ज.आ की अध्यक्षता में देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित की गई। बैठकमें तकनीकी समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, योजना की प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया और सामने आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं/ चुनौतियों (तकनीकी, वित्तीय, ई एंडएस सुरक्षा और खरीद पहलू) पर विस्तार से चर्चा की गई।

I. बाढ़ से संबंधित मामले

देश में बाढ़ की स्थिति - नवंबर 2024

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम बेसिन में 1 मई 2024 को नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि शुरू हुई। 1 मई से 30 नवंबर 2024 की अवधि के दौरान , कुल 10408 (7086 स्तर + 3322 अंतर्वाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 9943 (6790 स्तर + 3153 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 95.53% सटीकता के साथ स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। अक्टूबर 2024 के महीने के दौरान 141 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 124 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए। नवंबर माह2024 के दौरान केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से कोई रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए)जारी नहीं किया गया लेकिन 4 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2023 से 30.11.2024 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

छह एफएफ स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्रम सं.	राज्य	ज़िला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	असम	जोरहाट	ब्रह्मपुत्र	नेमाटीघाट	30/06/2024	02/07/2024
2		सोनितपुर	जियाभराली	जिया-भाराली एनटी रोड क्रॉसिंग	01/07/2024	01/07/2024
3		शिवसागर	दिखो	शिवसागर	02/07/2024	02/07/2024
4		डिब्रूगढ़	बुरीडीहिंग	खोवांग	02/07/2024	03/07/2024
5	बिहार	सीतामढ़ी	बागमती	धेंग ब्रिज	28/09/2024	29/09/2024
6		मुजफ्फरपुर	बागमती	रुनीसैदपुर	29/09/2024	30/09/2024

70 बाढ़ निगरानी केन्द्र पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई ।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 91 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई ।

असम, बिहार, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर-प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 128 मॉनिटरिंग स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, कर्नाटक और गुजरात के 50 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सीमा से अधिक अंतर्वाह प्राप्त करने वाले जलाशय

तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 77 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक जल प्रवाह प्राप्त हुआ।

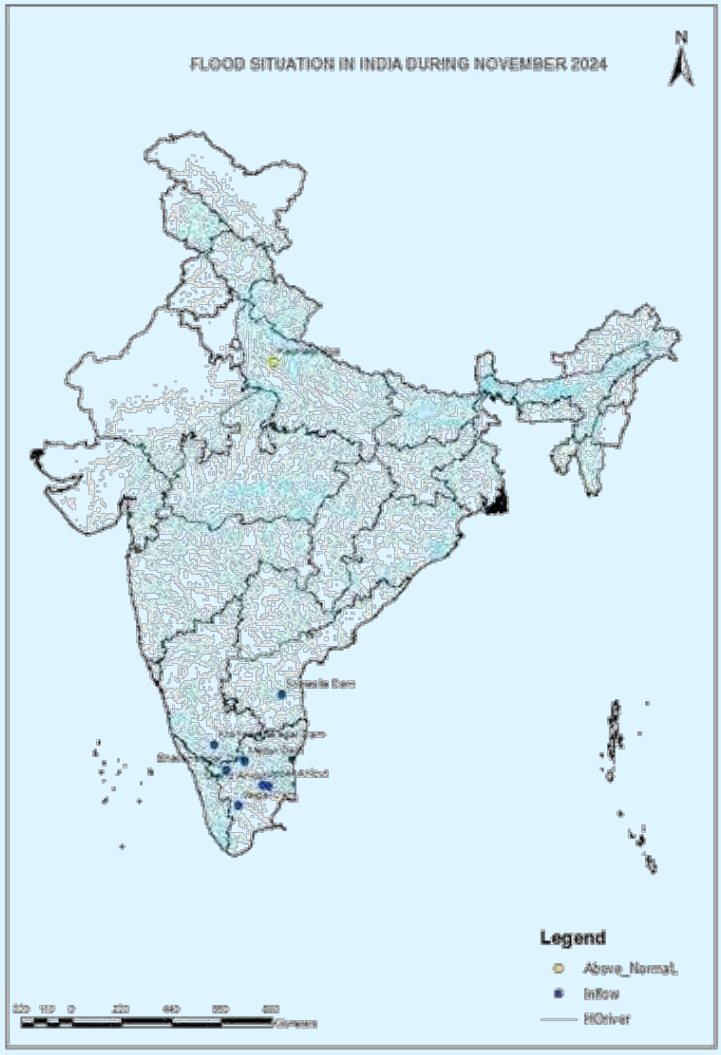

पृष्ठभूमि सामग्री/कार्ययोजना और आवश्यकताओं के साथ बाढ़ जलप्लावन मॉड्यूल की प्रस्तुति

9 अक्टूबर 2024 को बाढ़जलप्लावन मॉड्यूल पर केन्द्रीयजल आयोग केअध्यक्ष श्री राकेशकुमार वर्मा की अध्यक्षतामें एक बैठकआयोजित की गई।बैठक में जलसंसाधन, नदी विकासएवं गंगा संरक्षणविभाग तथा केन्द्रीयजल आयोग (मुख्यालय) के वरिष्ठअधिकारियों ने भागलिया। महानदी बेसिन, गंगाबेसिन, गोदावरी और तापीबेसिन के लिएपरामर्श/सहयोग के माध्यमसे मौजूदा/चल रहेजलप्लावन अध्ययनों की स्थितिप्रस्तुत की गई। अन्य बेसिनों के लिएडेटा आवश्यकता और जलप्लावनपूर्वानुमान के लिएकार्य योजना भी प्रस्तुतकी गई।

के.ज.आ के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहचाने गए बेसिनों में इन पहलों के कार्यान्वयन में एक कार्यक्रमिक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है और बाद में अन्य बेसिनों और राज्यों में इसका विस्तार किया जा सकता है। यह इच्छा व्यक्त की गई कि के.ज.आ के क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर सकते हैं ताकि राज्य सरकार स्तर पर किए जा रहे पूर्ण, चल रहे और प्रस्तावित बाढ़ मॉडलिंग अध्ययनोंसे संबंधित जानकारी एकत्रकी जा सके जिससे सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखों का उपयोग किया जा सके।

के.ज.आके अध्यक्ष ने इसबात पर जोरदिया कि किएजा रहे कार्योंकी लगातार समीक्षा मेंके.ज.आ को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिएतथा जहां भीआवश्यक हो, सुधार काप्रस्ताव करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चितकिया जा सकेकि अंतिम उत्पाद प्रस्तावित कार्यक्षमता के अनुरूपहो।

चिन्हित बेसिनों में बाढ़ जलप्लावन मानचित्रण के कार्यान्वयन और रोलआउट में प्रभावी सहयोग के लिए एक व्यवसायिक परियोजना निगरानीइकाई (पीएमयू) की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर प्रगति समीक्षा बैठकें

महानदी, गोदावरी और तापी बेसिन में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों की समीक्षा के लिए 28 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में दो बैठकें आयोजित की गईं।

महानदी बेसिन

पहली बैठकमें सी-डैक द्वाराकार्यान्वित "महानदी बेसिन मेंबाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालीके लिए समाधान" की समीक्षा की गई। के.ज.आ, सी-डैक औरक्षेत्रीय इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए।

सी-डैक टीमने बैठक में परियोजना की प्रगति प्रस्तुत की, जिसमें सॉफ्टवेयर क्षमताएं, उपयोग किएगए डेटा, कार्यप्रणाली और परिणामशामिल थे। इसमें होने वाली चर्चाएँ परिचालन उत्तरदायित्वों, परीक्षण, ओएंड एम औरमॉडल प्रदर्शन में सुधारपर केंद्रित थीं। सी-डैक कोइसी तरह केअंतरराष्ट्रीय प्रयासों (जैसे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया) में अंतर्दृष्टि प्रदान करने काकाम सौंपा गया था।

प्रमुखकार्य बिंदुओं में परिचालनचरणों के लिएउत्तरदायित्वों को परिभाषितकरना, बीटा लॉन्चसमय-सीमा औरप्रसार योजना विकसित करनातथा भविष्य में अन्य बेसिनों के विस्तारकी योजना बनाना शामिल था।

गोदावरी और तापी बेसिन

दूसरी बैठकमें राष्ट्रीय जल विज्ञानपरियोजना (एनएचपी) के तहतएनआरएससी, हैदराबाद द्वारा विकसितइन बेसिनों के लिए "स्थानिक बाढ़ पूर्वचेतावनी प्रणाली" की समीक्षाकी गई। इसमेंके. ज.आ, एनआरएससी और क्षेत्रीयइकाइयों के वरिष्ठअधिकारी शामिल हुए।

एनआरएससी टीम ने मॉडल अंशांकन, सत्यापन और डेटा सीमाओं सहित प्रगति प्रस्तुत की। चर्चाओं में मॉडल प्रदर्शन, परिचालन स्पष्टता और बीटा लॉन्च योजना में सुधार पर जोर दिया गया।

प्रमुखकार्य बिंदुओं में मॉडलअंशांकन और प्रदर्शनपर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उपयोगकर्ता मैनुअल प्रदान करना, परिचालन भूमिकाओं को परिभाषित करना (परीक्षण, ओएंडएम, समस्या निवारण), और भविष्यमें अन्य बेसिनों पर किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना बनाना शामिल था।

दोनों बैठकों में इनमहत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से संचालितकरने के लिए परिभाषित भूमिकाओं, कार्यान्वयन की समयसीमाऔर सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

झेलम नदी और सहायक नदियों पर व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यों के द्वितीय चरण से संबंधित सीडब्ल्यूपीआरएस के अध्ययन की स्थिति की निगरानी के लिए 9वीं और10 वीं बैठक

झेलम नदी और सहायक नदियों के लिए व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यों हेतु 9वीं और 10वीं बैठक क्रमश: 09.10.2024 और 21.11.2024 को सदस्य (आरएम), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

पहली बैठक में, सीडब्ल्यूपीआरएस ने अपनी मॉडल अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अशाम में बाढ़ के स्तर में मामूली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया, लेकिन अन्य स्टेशनों पर सुरक्षित स्तर की पुष्टि की गई।यह निर्णय लिया गया कि सीडब्ल्यूपीआरएस एफएससी को 80 मीटर चौड़ा करके अशाम में बाढ़ केस्तर को कमकरने के लिएआगे का अध्ययनकरेगा, जिसके परिणाम 20.10.2024 तक आनेचाहिए। एक क्षेत्र दौरा और अगली बैठक 20.10.2024 के बादश्रीनगर में होना निर्धारित किया गया।प्रमुख निर्णयों में एफएससीको चौडा करने की योजनाओंको अंतिम रूप देनाऔर क्षेत्र दौरा करने के बाद रिपोर्ट जमा करना शामिल था।

दूसरीबैठक के दौरान, सीडब्ल्यूपीआरएस के अधिकारियों ने 18 अक्टूबर 2024 तक केनवीनतम इनपुट डेटा के आधार पर झेलम नदी और सहायक नदियों पर व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्य -चरण II के लिए आयोजित1-डी मॉडलअध्ययनों के परिणाम प्रस्तुत किए। आईएंडएफसीडी जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों ने अपनी क्षेत्र संबंधी बाधाओं पर चर्चा की। गहन चर्चाके बाद, सदस्य (आरएम) ने सीडब्ल्यूपीआरएस को मौजूदा स्तर के अनुसार एफएससी ऑफटेक स्तर को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी।

एनएचपी के अंतर्गत गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ प्रणाली के संबंध में एईसीओएम के साथ बैठक

श्री राकेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष, के.ज.आ की अध्यक्षता में 4 नवंबर 2024 को दोपहर 3:00 बजे समिति कक्ष, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली में "गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली" पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

परामर्शकों में से वरिष्ठ सदस्य और के.ज.आ (मुख्यालय) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। एईसीओएम परामर्शकों की टीम ने परियोजना का अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें अब तक पूरे किए गए कार्यों और कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों का विवरण दिया गया।

एईसीओएम की टीम ने वास्तविक समय के आधार पर (प्रतिदिन एक या दो बार) जलप्लावन पूर्वानुमान मॉडल चलाने, उच्च-रिज़ॉल्यूशन डीईएम के उपयोग तथा सॉफ्टवेयर व् हार्डवेयर से संबंधित बाधाओं जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। अध्यक्ष ने एईसीओएम को मौजूदा मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीके तलाशने और प्रस्तावित समाधान प्रस्तुत करने की सलाह दी।

एनईएसएसी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली / बाढ़ जलप्लावन अध्ययन के संबंध में बैठक

पूर्वोत्तर क्षेत्रमें बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली / बाढ़ जलप्लावनअध्ययन के संबंधमें एनईएसएसी टीम केसाथ सदस्य (आरएम) श्री एएसगोयल की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई।

डॉ. एसपी अग्रवाल (निदेशक, एनईएसएसी) और डॉ. दिगंत बर्मन (वरिष्ठ वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसएफ) ने बैठक में भाग लिया। बैठक में के ज.आ (मुख्यालय) और क्षेत्रीय इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

एनईएसएसीटीम ने असमराज्य के लिएविकसित बाढ़ पूर्वचेतावनी प्रणाली प्रस्तुत कीजो 12-48 घंटों की समय सीमा के साथ राजस्व सर्कल स्तरपर बाढ़ कीचेतावनी प्रदान करती है।मॉडल की सीमा, मुद्दे, चुनौतियाँ और प्रणालीमें सुधार के लिएआगे के रास्तेपर विस्तार से चर्चाकी गई।

II. अंतर्राज्यीय विवाद

विभिन्न अंतर्राज्यीय मुद्दों पर प्रस्तुति

विभिन्न अंतर्राज्यीय मुद्दों के संबंध में 29 अक्टूबर, 2024 को के.ज.आ के अध्यक्ष द्वारा एक बैठक की गई । बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सदस्य (डी एंड आर), सीई (आईएमओ), सीई (पीएओ) और निदेशक (आईएसएम-1) ने भाग लिया। सीई (आईएमओ) ने अंतर-राज्यीय मुद्दों ,जैसे अंतर-राज्यीय विवादों के संबंध में के.ज.आ की भूमिका;मौजूदा अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद; हाल के दिनों में के.ज.आ द्वारा निपटाए गए अंतर-राज्यीय मुद्दे; परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनसे उत्पन्न होने वाले अंतर-राज्यीय मुद्दे; जल संसाधनों के वितरण और प्रबंधन से संबंधित अंतर-राज्यीय नदी मुद्दे और डब्ल्यूपी एंड पी विंग के अलावा के.ज.आ के विंग/संगठनों द्वारा निपटाए जा रहे अंतर-राज्यीय नदी मुद्दे से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को शामिल करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया है।

प्रस्तुति के दौरान, पीपीटी में प्रस्तुत विषयों पर अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ चर्चा की। के.ज.आ के अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि अंतर-राज्यीय पहलुओं का समाधान न होने के कारण के.ज.आ में लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की जाए तथा ऐसी परियोजनाएं, जिनके मामले न्यायाधिकरणों/ न्यायालयों में विचाराधीन हैं, उन्हें परियोजना प्राधिकरणों को वापस भेजा जाना चाहिए।

III.पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी & डब्लूएम

पीएमकेएसवाई योजना की समीक्षा के लिए बैठक

पीएमकेएसवाई योजना की समीक्षा बैठक 08.10.2024 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) के सचिव ने की।

इस बैठक में आयुक्त (एसपीआर) द्वारा वर्तमान स्थिति, कार्य योजना और बाधाओं पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के बाद अधिकारियों द्वारा चिह्नित आंकड़ों और मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए की गई चर्चाओं और उनके बाद लिए गए निर्णयों का सारांश नीचे दिया गया है।

1. 2016-21 के दौरान, 46 पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाएं पूरी हुईं और पीएमएसकेवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के माध्यम से 22.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई।
2. 2021-26 के दौरान कुल 23,918 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें एआईबीपी के लिए 18,352 करोड़ रुपये और सीएडीडब्ल्यूएम के लिए 5,566 करोड़ रुपये शामिल हैं।
3. 2,476 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है, नई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के लिए 5,784 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि राष्ट्रीय परियोजना के लिए 9,292 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
4. 3,900 करोड़ रुपये की पात्र केन्द्रीय सहायता वाली 10 परियोजनाएं पहले ही शामिल की जा चुकी हैं, जबकि 6,900 करोड़ रुपये की पात्र केन्द्रीय सहायता वाली छह परियोजनाएं शामिल किए जाने के लिए प्रक्रिया में हैं।
5. 2021-24 के दौरान 16 और परियोजनाएं पूरी हुईं, जिससे पूरी हो चुकी परियोजनाओं की संख्या 62 हो गई और 44 परियोजनाएं शेष है। शेष 44 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। ये परियोजनाएं मार्च 2025 तक पूरी हो सकती हैं। अन्य 7 परियोजनाएं 2025-26 के दौरान पूरी हो सकती हैं। हालांकि, 12 परियोजनाओं के वित्त वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, के.ज.आ के अध्यक्ष के अधीन समिति ने शेष 14 परियोजनाओं को बंद करने की सिफारिश की है।
6. अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि सबसे पहले संबंधित राज्य सरकारों के साथ 11 अग्रिम चरण की परियोजनाओं की समीक्षा की जाए, तत्पश्चात बंद करने हेतु सिफारिश की गई 14 परियोजनाओं और उसके बाद शेष 19 परियोजनाओं की समीक्षा की जाए।

बैठक भौतिक रूप से आयोजित की गई, इस बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग , ii) सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) के.ज.आ, iii) मुख्य अभियंता पीएमओ, के.ज.आ और iv) निदेशक, एमओएन-सी डीटीई , पीएमओ, के.ज.आने भाग लिया।

उन्नत चरण की 11 पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की समीक्षा (उनके सीएडीडब्ल्यूएम घटकों के साथ)

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों, के.ज.आ (मुख्यालय) और के.ज.आ की फील्ड इकाई के अधिकारियों के साथ मुद्दों / बाधाओं (यदि कोई हो) पर चर्चा करने के लिए 14.11.2024 को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 11 उन्नत चरण की परियोजनाओं (उनके सीएडीडब्ल्यूएम घटकों के साथ) जैसे (आंध्र प्रदेश: 01; कर्नाटक: 01; मध्य प्रदेश: 02; महाराष्ट्र: 03; मणिपुर: 01; ओडिशा: 01; तेलंगाना: 01 और उत्तर प्रदेश: 01) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जलशक्ति मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालय, के.ज.आको उन परियोजनाओं का दौरा करने का निर्देश दिया जिनकेमार्च-2025 से आगे तकलंबित रहने की संभावना है और परियोजना के एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम घटकों को शीघ्र पूरा करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। क्षेत्र दौरा रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं की एक और समीक्षा बैठक जनवरी-2025 में आयोजित की जाएगी। शेष परियोजनाओं के संबंध में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव ने परियोजना प्राधिकरण को निर्देश दिया कि जैसे बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था उसी अनुसार परियोजना को निर्धारित तिथि पर पूरा करना सुनिश्चित करें।

बैठक भौतिक / हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी, इस बैठक में i) अध्यक्ष, के.ज.आ, अपर सचिव, के.ज.आ ,सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, ii) सदस्य ((डब्ल्यूपी&पी), के.ज.आ iii) मुख्य अभियंता, पीएमओ, केन्द्रीय जल आयोग और iv) निदेशक, मॉनिटरिंग-सेल निदेशालय, पीएमओ, केन्द्रीय जल आयोग।

11 परियोजनाओं में से एक परियोजना, थौबल बहुउद्देशीय परियोजना (मणिपुर), जो मोन (ईएंडडब्ल्यू) में शामिल है, पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। हीरॉक शाखा नहर के संबंध में 1.95 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का मुद्दा लंबे समय से लंबित है, जिसे मणिपुर के जल संसाधनविभाग के सचिव संज्ञान में लाए और बताया कि परियोजना को पूरा होने में मार्च 2025 से आगे यानी जून 2025 तक का समय लग सकता है ।

अध्यक्ष ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

IV. अन्य गतिविधियां

एनएचपी के तहत एकीकृत जलाशय संचालन पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति

गंगा बेसिन के लिए लगभग वास्तविक समय एकीकृत जलाशय संचालन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस)के विकास के लिए प्रगति समीक्षा बैठक 17 अक्टूबर 2024 को सेवा भवन स्थित के.ज.आ समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार वर्मा ने की।

बैठक की शुरुआत अध्यक्ष के स्वागत भाषण से हुई। उसके बाद निदेशक एफएफएम ने परियोजना का अवलोकन प्रस्तुत किया, जो गंगा बेसिन में एकीकृत जलाशय संचालन पर केंद्रित है। प्रस्तुति में डीएसएस विकास के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया, जिसके बाद डीएसएस डैशबोर्ड का लाइव प्रदर्शन किया गया।

बैठक की शुरुआत अध्यक्ष के स्वागत भाषण से हुई। उसके बाद निदेशक एफएफएम ने परियोजना का अवलोकन प्रस्तुत किया, जो गंगा बेसिन में एकीकृत जलाशय संचालन पर केंद्रित है। प्रस्तुति में डीएसएस विकास के प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया, जिसके बाद डीएसएस डैशबोर्ड का लाइव प्रदर्शन किया गया।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दूसरी तिमाही वार्ता

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएंडएसआरओ, के.ज.आ कोयंबटूर, सीएमडीडी निदेशालय (ईएंडएनई) के निदेशक और उनकी टीम के साथ-साथ सीजीडब्ल्यूबी और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

1. धनिखरी जलाशय का अवसादन अध्ययन ।
2. लिटिल अंडमान में स्थित दो बांधों में रिसाव की समस्या।
3. खुदीरामपुर , डिगलीपुर में कलपोंग नदी पर एक बांध का निर्माण ।
4. गुप्तापाड़ा बांध के लिए डीपीआर तैयार करना ।
5. कोरंग नाला बांध के लिए परियोजना दस्तावेजों की जांच ।
6. कोइला नाला परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करना।
8. फ्लैट बे झील परियोजना के लिए डीपीआर तैयार करना।
8. जल संसाधन क्षेत्र में एपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण।

केंद्रीय जल आयोग और उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।

दिनांक 10.10.2024 को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) मुख्यालय में उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (यूपीडीसीसी) लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, के.ज.आ ने यूपीडीसीसी को सौंग बांध के निर्माण के लिए समीक्षा डिजाइन परामर्श सेवाएं प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

सोंग बांध परियोजना में सोंग नदी पर 130.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध शामिल है, जो देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों की सीमा पर सोंधना गांव के पास स्थित है, जो मालदेवता से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 25 किलोमीटर दूर है। इस पेयजल परियोजना का उद्देश्य देहरादून शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों की घरेलू पानी की मांग को पूरा करना है।

निदेशक, सीएमडीडी (ईएंडएनई), के.ज.आऔर महाप्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू), सोंग, यूपीडीसीसी लिमिटेड, उत्तराखंड ने श्री भोपाल सिंह, सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग देश के 155 जलाशयों की जल संग्रहण स्थिति की निगरानी कर रहा है तथा प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय जलविद्युत परियोजनाओं के हैं, जिनकी कुल जल संग्रहण क्षमता 35.299 बीसीएम है। 155 जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 180.852 बीसीएम है, जो देश में अनुमानित 257.812 बीसीएम जल संग्रहण क्षमता का लगभग 70.15% है।

दिनांक 28.11.2024 के जलाशय संग्रहण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रहण की स्थिति 147.943 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय संग्रहण क्षमता का 82% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रहण की स्थिति 117.4 बीसीएम थी और पिछले 10 वर्षों का औसत सक्रिय संग्रहण 126.916 बीसीएम था।

इस प्रकार, 28.11.2024 के बुलेटिन के अनुसार 155 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रहण की स्थिति पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय संग्रहण की स्थिति का 126% और पिछले दस वर्षों के औसत सक्रिय संग्रहण का 117% है।

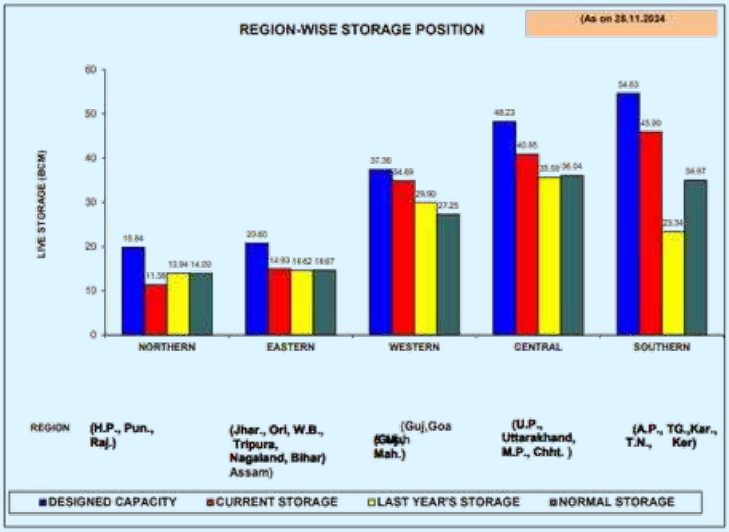

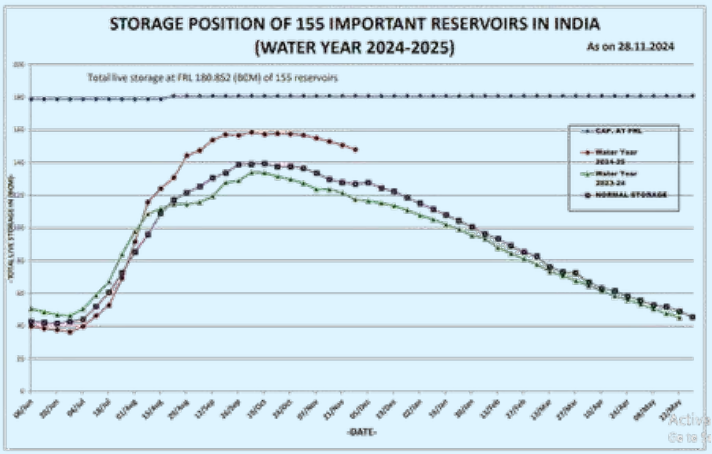

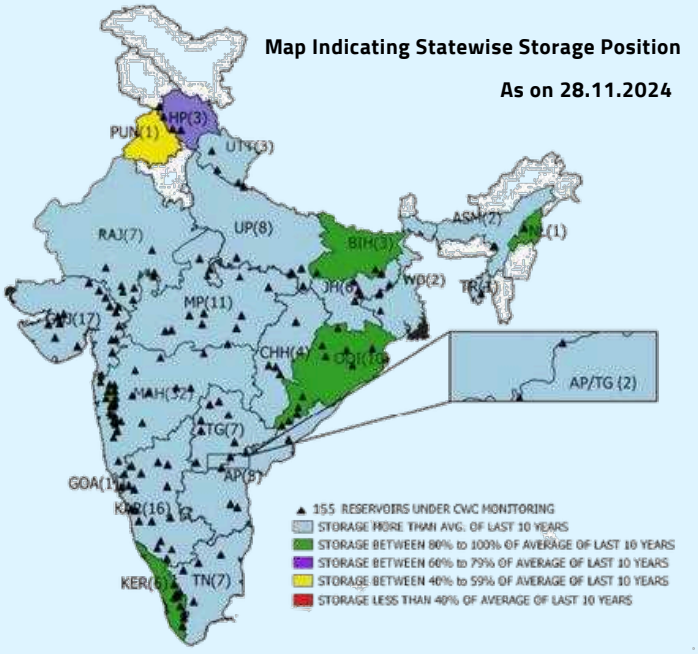

Map Indicating Statewise Storage Position

As on 28.11.2024

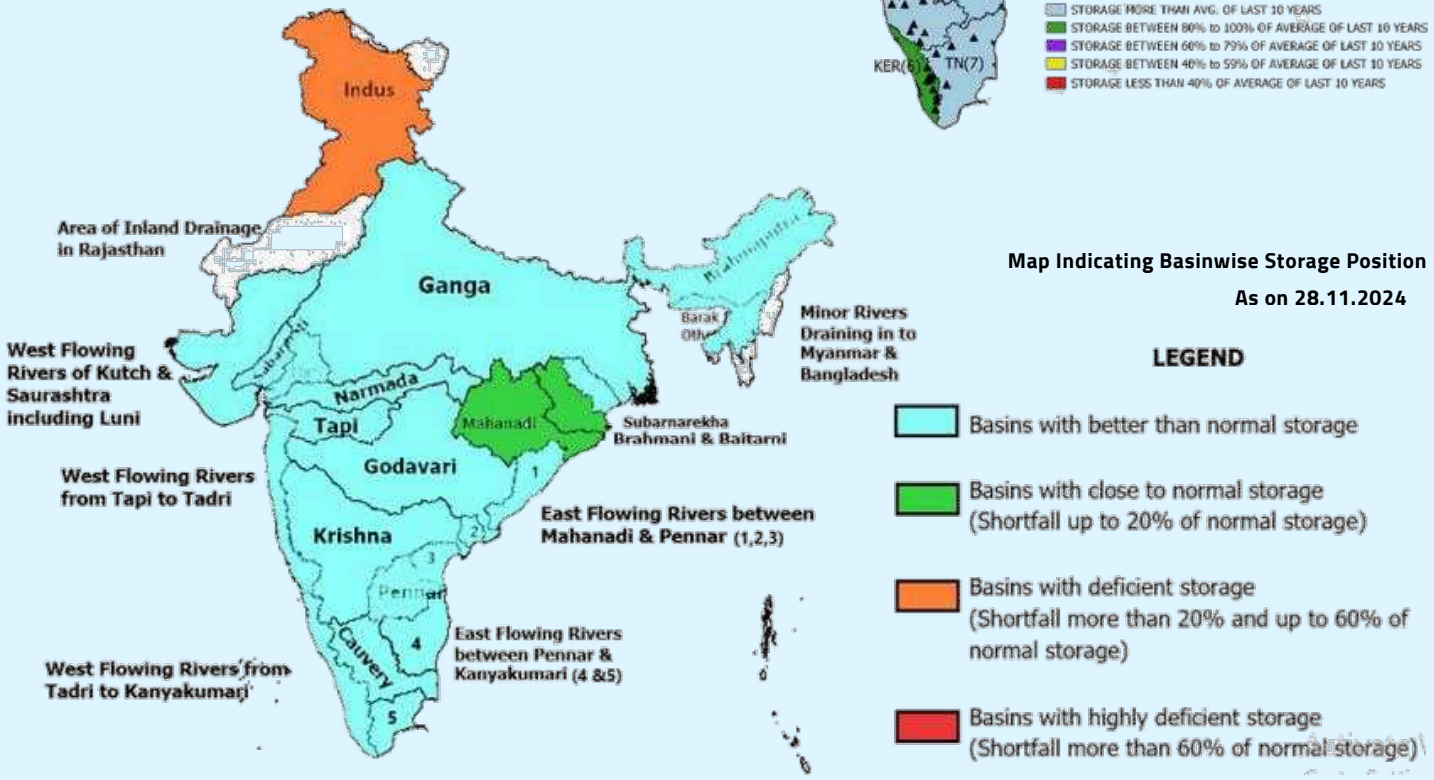

Map Indicating Basinwise Storage Position

As on 28.11.2024

दीर्घा

स्मार्ट जल संसाधन मॉडलिंग संगठन (उत्कृष्टता केंद्र), सीडब्ल्यूसी द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला सीडब्ल्यूसी और डेनमार्क के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ जीएलओएफ मॉडल अध्ययन, बाढ़ पूर्वानुमान और जलप्लावन मॉडलिंग और विस्तारित जल विज्ञान पूर्वानुमान (ईएचपी) जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नर्मदा बेसिन संगठन , भोपाल के अधीनस्थ उपमंडल मध्य नर्मदा उपमंडल इंदौर -3 द्वारा आज दिनांक 28/10/2024 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह (28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024) के अंतर्गत ग्राम दुधिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

Gallery

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की 9वीं बैठक 7 नवंबर, 2024 को सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे पर चर्चा की गई।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर, 2024 को कौशल भवन, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली के सभागार में "एकीकृत बाढ़ जोखिम प्रबंधन" पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई है। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री देबाश्री मुखर्जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री भूपिंदर सिंह , मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. गंगवार , निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री रवि रंजन , निदेशक (डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in